हेमंत सोरेन से कांग्रेस प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष, मंत्रियों और विधायकों ने की मुलाकात

सरकार संवेदनशीलता से युवाओं पर निर्णय लेती रहेगी : मुख्यमंत्री

रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मंगलवार को कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में झारखंड प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के. राजू, प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश समेत कांग्रेस के मंत्रियों और विधायकों ने मुलाकात की। नेताओं ने 17 अगस्त को हुई कैबिनेट की विशेष बैठक में छात्र और अभ्यर्थी हित में लिए गए फैसलों का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताया।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कांग्रेस नेताओं से मुलाकात के दौरान छात्रों की मांगों पर लिए गए फैसलों पर कहा है कि राज्य सरकार का उद्देश्य झारखंड के युवाओं और विद्यार्थियों के हितों की रक्षा करना है। उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य से जुड़े विषयों पर राज्य सरकार पूरी तरह संवेदनशीलता और गंभीरता के साथ निर्णय लेती रही है, आगे भी लेती रहेगी।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री के साथ राज्य में चल रहे विकासात्मक योजनाओं, जनहित एवं छात्र कल्याण से जुड़े विभिन्न विषयों पर भी विस्तृत संवाद हुआ। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि सरकार के इन निर्णयों से प्रभावित विद्यार्थियों को राहत मिलेगी और उनके भविष्य को लेकर बनी अनिश्चितता दूर होगी। इन निर्णयों से सरकार की प्रतिबद्धता और संवेदनशील पहल की सराहना की।

मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में मंगलवार को सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात करते झारखंड प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के. राजू, प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, मंत्री इरफान अंसारी, मंत्री दीपिका पांडेय सिंह समेत कांग्रेस के मंत्री और विधायक।

- कैबिनेट की विशेष बैठक में लिए निर्णयों पर जताया मुख्यमंत्री का आभार
- राज्य में चल रही योजनाओं और छात्र कल्याण से जुड़े विभिन्न विषयों पर संवाद

विद्यार्थियों के हितों में महत्वपूर्ण कदम : कांग्रेस

कांग्रेस नेताओं ने संयुक्त रूप से कहा कि राज्य सरकार का यह निर्णय विद्यार्थियों और अभ्यर्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री से उन्होंने कहा कि आपके नेतृत्व में राज्य सरकार जनहित और युवाओं के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। टीडीपीएल द्वारा आयोजित परीक्षाओं को रद्द करने के निर्णय से प्रभावित विद्यार्थियों एवं अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी। उनके भविष्य को लेकर उत्पन्न अनिश्चितता भी दूर होगी।

मौके पर मुख्यमंत्री ने झारखंड प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के. राजू, झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश सहित कांग्रेस के मंत्रियों और विधायकों के प्रति धन्यवाद व्यक्त किया।

इस दौरान मंत्री इरफान अंसारी, मंत्री दीपिका पांडेय सिंह, मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, विधायक कल्पना सोरेन, विधायक रामेश्वर उरांव, विधायक प्रदीप यादव, विधायक कुमार जयमंगल, विधायक राजेश कच्छप, विधायक रामचंद्र सिंह, विधायक नमन विक्सल कोनगाड़ी, विधायक भूषण बाड़ा और विधायक ममता देवी सहित अन्य उपस्थित रहे।

परीक्षा में सुधार के लिए ठोस रणनीति बनाएगी कांग्रेस

रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की मंगलवार को झारखंड विधानसभा सभागार में बैठक हुई। बैठक में राजनीतिक मामलों की कमेटी ने विगत 24 दिनों से चल रहे छात्र आंदोलन में सरकार की ओर से लिये गए निर्णय के संबंध में प्रस्ताव पारित कर लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मंत्रियों और विधायकों को धन्यवाद दिया।

कांग्रेस के झारखंड प्रभारी के. राजू ने कहा कि भर्ती परीक्षा में सुधार के संबंध में पार्टी एक ठोस रणनीति बनाने के लिए स्टडी करेगी और सरकार को सुझाव देगी। खनन विधेयक के खिलाफ पार्टी आंदोलन चलाएगी। आंदोलन की रूपरेखा तय करने के लिए सभी सदस्यों से सुझाव लिया जाएगा। विस्थापन और भूमि अधिग्रहण पर कांग्रेस सरकार के सामने अपने सुझावों को रखेगी और 2013 के कानून को पूरी तरह अमल करने पर पार्टी जोर देगी। परिसीमन पर भी पार्टी विचार करके संघर्ष करने को तैयार है। कांग्रेस विधायक दल नेता प्रदीप यादव ने कहा कि जब जाति जनगणना प्रारंभ होगी तो हम ओबीसी के कॉलम को रखेंगे।

संघर्ष के लिए तैयार रहें कार्यकर्ता : केशव

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि आने वाले दिन झारखंड की जनता और कांग्रेस के लिए चुनौतियों भरा समय रहेगा। हमें संघर्ष के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है। केंद्र सरकार द्वारा झारखंड की हकमारी की जा रही है। खनन विधेयक से झारखंड को व्यापक नुकसान होगा। इसके खिलाफ अगर हमें आर्थिक नाकेबंदी भी करनी पड़ी तो पार्टी इससे पीछे नहीं हटेगी।

'बाबूलाल भाजपा शासित राज्यों के छात्र आंदोलनों पर दें ध्यान'

रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। कांग्रेस के प्रदेश महासचिव आलोक दुबे ने कहा कि जहां तक सीबीआई जांच की बात है, पूरा देश देख चुका है कि सीबीआई सहित कई लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वायत्तता को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। केंद्र सरकार पर संस्थाओं के दुरुपयोग के आरोप किसी से छिपे नहीं हैं। झारखंड में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी को सीबीआई जांच की मांग करने से पहले भाजपा शासित राज्यों में चल रहे छात्र और युवा आंदोलनों पर भी ध्यान देना चाहिए।

वहीं, कांग्रेस के महासचिव विनय सिन्हा ने कहा कि हमारी महागठबंधन सरकार छात्रों की आवाज सुनने और पारदर्शी व्यवस्था कायम करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। जो विपक्षी दल इस संवेदनशील मुद्दे पर केवल राजनीतिक रोटियां सेंकने में लगे थे, उन्हें राज्य के जागरूक युवाओं ने करारा जवाब दे दिया है।

सियासत 360°

झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रबीन्द्रनाथ महतो से उनके आवास पर मंगलवार को मुलाकात करते दिल्ली विस अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता और उनकी धर्मपत्नी डॉ. शोभा विजेंद्र।

दिल्ली विस अध्यक्ष रबीन्द्रनाथ से मिले

रांची। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता और उनकी धर्मपत्नी डॉ. शोभा विजेंद्र ने मंगलवार को झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रबीन्द्रनाथ महतो से उनके आवास पर औपचारिक भेंट की। इस दौरान स्पीकर महतो ने उन्हें भगवान बिरसा मुंडा की स्मृति-चिह्न और अपनी पुस्तक 'सदन संवाद' भेंट की। उन्होंने कहा कि यह मुलाकात महज औपचारिकता नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों, संसदीय परंपराओं और आपसी सौहार्द की सुंदर अभिव्यक्ति है।

मुख्यमंत्री का निर्णय ऐतिहासिक : मनोज

रांची। प्रदेश राजद प्रवक्ता डॉ. मनोज कुमार ने कहा कि राज्य सरकार छात्रों के प्रति बेहद गंभीर और संवेदनशील है। छात्रों की मांगों पर सकारात्मक रुख अपनाते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने छात्र हित में ऐतिहासिक निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकारों में भी कई घोटाले हुए, लेकिन भाजपा सरकार कभी भी ऐसा साहसिक निर्णय नहीं ले सकी। भाजपा केवल जनता को भ्रमित करना जानती है।

सरकार छात्र हित के प्रति संवेदनशील : शाहदेव

रांची। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव सह मीडिया विभाग के संयोजक लाल किशोरनाथ शाहदेव ने नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के बयानों पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि राज्य की हेमंत सोरेन सरकार युवाओं और छात्रों के हितों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है, जबकि भाजपा सिर्फ हर मुद्दे पर राजनीति करने में लगी है। राहुल गांधी हमेशा युवाओं, रोजगार और न्याय की लड़ाई लड़ते हैं।

प्रोफेशनल्स कांग्रेस का त्रैमासिक न्यूज लेटर जारी

रांची। झारखंड प्रदेश प्रोफेशनल्स कांग्रेस के त्रैमासिक न्यूज लेटर का मंगलवार को विमोचन किया गया। इसमें पार्टी संगठन के प्रमुख कार्यक्रमों, बैठकों, धरना-प्रदर्शन, आंदोलनों और अन्य सांगठनिक गतिविधियों को प्रकाशित किया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस महासचिव सह प्रोफेशनल्स प्रभारी आदित्य विक्रम जायसवाल ने कहा कि झारखंड के पास भरपूर संसाधन हैं, पर अवसरों की कमी है।

राहुल ने छात्रों की मांगें गंभीरता से लीं : नायक

रांची। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता विजय शंकर नायक ने छात्र हित में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से लिये गए फैसलों का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी लगातार देश के युवाओं के रोजगार और न्याय की आवाज मजबूती से उठा रहे हैं। झारखंड में भी छात्रों की मांगों को उन्होंने गंभीरता से लिया। प्रदेश कांग्रेस लगातार छात्रों के साथ खड़ी रही।

केंद्र एनटीए से परीक्षाएं करवाना बंद करे : राजीव

रांची। कांग्रेस के मीडिया पैनलिस्ट डॉ. राजीव नारायण प्रसाद ने कहा कि एनटीए अयोग्य व असक्षम है। एनटीए ने तीन महीने पहले ही यूजीसी नेट की परीक्षा ली थी, जिसमें से तीन विषयों की परीक्षा दोबारा ली जा रही है। क्योंकि प्रश्न पत्र में गड़बड़ियां मिलीं। एनटीए ने नीट की परीक्षा भी ली थी, जिसमें पेपर लीक हुआ था। केंद्र सरकार को एनटीए से सभी परीक्षाएं लेना तुरंत बंद करवा देना चाहिए।

सोशल मीडिया से

प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने एक्स पर पोस्ट किया- नई दिल्ली में संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, कर्नाटक कांग्रेस के प्रभारी आरएस सुरजेवाला व अन्य के साथ मैसूर ग्रामीण जिला कांग्रेस के जिलाध्यक्ष के पैनल में शामिल नामों पर चर्चा की। कांग्रेस अध्यक्ष और नेता विपक्ष राहुल गांधी ने एक बेहतरीन पहल की है, जिसके माध्यम से जमीनी स्तर से जुड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं को जिला स्तर पर नेतृत्व प्रदान करने का प्रयास है। मुझे विश्वास है कि हम नेतृत्व के विश्वास पर खरा उतरेंगे।

11 हजार एनएचएम कर्मियों को मिलेगा ईपीएफ का लाभ

रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा व परिवार कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में मंगलवार को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा सहित विभाग व मिशन के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में एनएचएम कर्मियों के ईपीएफ, बजट, ममता वाहन, तंबाकू नियंत्रण, नेत्र जांच, कुष्ठ रोग नियंत्रण सहित मानव संसाधन से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई।

बैठक में एनएचएम की ओर से बताया गया कि राज्य में 15 हजार रुपये से कम मानदेय पाने वाले कर्मियों के लिए ईपीएफ लागू है, लेकिन 15 हजार रुपये से अधिक मानदेय पाने वाले कर्मी इसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। इस पर अपर मुख्य सचिव ने संशोधित प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया। उन्होंने 15 हजार रुपये को बेसलाइन मानते हुए अधिक मानदेय पाने वाले कर्मियों को भी ईपीएफ के दायरे में शामिल करने का प्रस्ताव देने को कहा। प्रस्ताव लागू होने पर राज्य के 11 हजार से अधिक एनएचएम कर्मियों को इसका लाभ मिलने की संभावना है। बैठक में यह भी बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए भारत सरकार ने झारखंड एनएचएम का 3124.75 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया है।

सीएचसी में आंखों की जांच के लिए लगेगी मशीन

सीएचसी स्तर पर आंखों की जांच की सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। प्रत्येक सीएचसी में आंखों की जांच के लिए मशीन उपलब्ध कराई जाएगी और जरूरतमंद मरीजों को चश्मा भी वितरित किया जाएगा।

पीएम के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट थाने में शिकायत

रांची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी और पोस्ट करने के मामले में ऋषिकेश चौहान समेत अन्य के विरुद्ध साइबर थाना में शिकायत दर्ज की गई है।

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अजय साह की ओर से थाना में आवेदन दिया गया है। इसमें आरोप लगाया गया है कि सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री के खिलाफ अपमानजनक पोस्ट व टिप्पणी की गई है। ऋषिकेश चौहान नामक व्यक्ति द्वारा कांग्रेस महानगर के अध्यक्ष कुमार राजा के इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर टिप्पणी की गई है।

अजय साह ने कहा कि देशद्रोह के तहत केस दर्ज कर जेल भेजा जाए। आरोपियों द्वारा माहौल बिगाड़ने का भी प्रयास है। पुलिस ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। आरोपियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए।

खनन विधेयक, छात्र आंदोलन और परिसीमन पर शाह आज करेंगे बैठक

रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। झारखंड में खान खनिज संशोधन बिल के बाद झामुमो समेत अन्य सत्ताधारी दलों के विरोध से निपटने की रणनीति पर बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बैठक करेंगे। इस दौरान झारखंड में चल रहे छात्र आंदोलन के साथ-साथ राज्य में संभावित परिसीमन को लेकर भी चर्चा होगी।

बैठक में झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह, पूर्व सीएम रघुवर दास, अर्जुन मुंडा, चंपाई सोरेन, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व झारखंड में कोर कमेटी के नेता रवींद्र राय, दीपक प्रकाश को भी शामिल होने के लिए बुलाया गया है। बैठक में छात्रों के आंदोलन के राजनीतिक प्रभावों की चर्चा भी की जाएगी। वर्तमान में राज्य सरकार ने जेपीएससी 14वीं, सीजीएल समेत अन्य परीक्षाओं के रद्द होने की घोषणा कर दी है। छात्रों के विषय में भी भाजपा आगे किस रणनीति पर कार्य करेगी, यह फैसला लिया जाएगा। राज्य में परिसीमन को लेकर भी बैठक में चर्चा होगी। राज्य में पूर्व में परिसीमन 2006 से लंबित है, जिसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर रोका गया था। लेकिन, जनगणना के बाद नए सिरे से परिसीमन प्रस्तावित है।

भाजपा के आठ नेताओं के साथ एक घंटे होगी बैठक

झामुमो के विरोध से निपटने की भाजपा बनाएगी रणनीतिः खान खनन संशोधन विधेयक के पास होने के बाद झामुमो व कांग्रेस काफी आक्रामक है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कैबिनेट की बैठक के बाद उच्चस्तरीय बैठक बुलाने व विधानसभा के विशेष सत्र के आयोजन की घोषणा की थी। मंगलवार को भी कांग्रेसी नेताओं के साथ बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कांग्रेस नेताओं से बिल के विरोध में आवाज उठाने व आंदोलन की बात कही।

झामुमो व कांग्रेस के द्वारा सेस वसूलने के अधिकार के खत्म होने पर सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं को प्रभावित होने को लेकर विरोध दर्ज कराया गया है। पूरे मामले में झारखंड भाजपा की रणनीति क्या होगी, भाजपा इस आंदोलन को लेकर किस तरह से जनता के बीच पक्ष रखेगी, इन विषयों पर आठो नेताओं से गृह मंत्री चर्चा करेंगे।

जेपीएससी के तीन अभ्यर्थी रिमांड पर

रांची। सीआईडी ने जेपीएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितता से जुड़े केस 16/26 में तीन सफल अभ्यर्थियों मनोज कुमार, रोशन केरकेट्टा और उमाकांत उरांव को पूछताछ के लिए पांच दिनों की रिमांड पर लिया है। सीआईडी द्वारा जेपीएससी 14वीं परीक्षा में कथित अनियमितता की स्क्रूटनी दो दिनों में पूरी कर ली जाएगी। सीआईडी को 2204 सफल अभ्यर्थियों में 1700 से अधिक ओएमआर शीट का मिलान करना है। जेपीएससी से जब्त मूल ओएमआर शीट और सफल अभ्यर्थियों से मिले कार्बन ओएमआर शीट का मिलान किया जाएगा।

E-mail:- monitoring@sfcjharkhand.in
Jharkhand State Food and Civil Supplies Corporation Limited.
(A Government of Jharkhand Undertaking)
JSFC Bhawan, Kadru, Main Road, Ranchi-834002
NIT No.- 2512 Date:- 18/08/2026
Corrigendum for Tender serial No. 2393, dated 06.08.2026 are available on the website Jharkhand.gov.in -> Department -> Food, Public Distribution & Consumer Affairs -> Tender & Corrigendum.

अधिसूचना का इंतजार, छात्रों का अनशन जारी

रांची, वरीय संवाददाता। जेपीएससी-जेएसएससी परीक्षा में कथित भ्रष्टाचार और अनियमितता के विरोध में जयपाल सिंह मंडा स्टेडियम में छात्रों का आंदोलन 25वें दिन मंगलवार को भी जारी रहा। दिनभर बारिश के बीच छात्र सरकार के फैसले को लेकर आधिकारिक अधिसूचना के इंतजार में रहे।

वहीं आगे के आंदोलन को लेकर भी चर्चा करते रहे। फिलहाल 20 अगस्त को प्रस्तावित मुख्यमंत्री आवास का घेराव कार्यक्रम स्थगित रखा गया है। प्रदर्शन स्थल पर तीन छात्र-छात्राओं का अनशन 14 वें दिन भी जारी रहा। इसमें राहुल, सबिता, रूपेश पाल शामिल हैं। जेपीएससी-जेएसएससी रिफॉर्म मंच के रवींद्र पासवान व पीयूष कुमार ने बताया कि छात्र सरकार के निर्णय के बाद नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं। अधिसूचना जारी होने पर देखा जाएगा कि कौन-कौन सी परीक्षा सरकार ने रद्द की है।

विवादित परीक्षा रद्द होना ऐतिहासिक जीत : देवेंद्र

जयपाल सिंह स्टेडियम में मंगलवार को प्रेसवार्ता में जानकारी देते देवेंद्रनाथ।

देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि झारखंड में विवादित सभी परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है, जो भारत के सबसे बड़े छात्र आंदोलनों में से एक की ऐतिहासिक जीत है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय छात्र हित में सरकार द्वारा लिया गया एक बड़ा और सकारात्मक कदम है। वे आंदोलन स्थल पर प्रेस वार्ता में बोल रहे थे। उन्होंने बताया कि अब अगली लड़ाई नई और पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था लागू कराने की है, अगर कोई धांधली का हिम्मत करता है तो उसे पकड़कर आजीवन कारावास तथा हर योग्य अभ्यर्थी को उसकी मेधा और निष्पक्ष प्रक्रिया के आधार पर नौकरी मिलने की गारंटी हो।

20 अगस्त को प्रस्तावित मुख्यमंत्री आवास घेराव कार्यक्रम स्थगित

तिरंगा यात्रा रोकने पर गवर्नर से जांच की मांग

छात्र आंदोलन में लगातार अनशन पर बैठने वाले छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर तिरंगा यात्रा एवं ध्वजारोहण से रोके जाने को लेकर एक प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को राज्यपाल संतोष गंगवार से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने पूरे मामले की जांच की मांग की।

जेपीएससी और नगड़ी थाने ने नहीं की कार्रवाई

खुलासा

- अभय तिवारी व टीडीपीएल के खिलाफ मिली थी शिकायत
- एल ख्यांग्ते को एक जनवरी को ही मिली थी शिकायत

रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। जेपीएससी की परीक्षाओं में धांधली को लेकर मिली शुरुआती शिकायतों को पूरी तरह दरकिनार किया गया था। हालांकि बाद में सीआईडी ने इन सारे तथ्यों को अपनी जांच में समाहित किया है। जानकारी के मुताबिक, जेपीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष एल ख्यांगते को 1 जनवरी 2026 को ही शिकायत मिल गई थी, यह शिकायत कर्नाटक थर्ड क्रॉस रोड निवासी सौरभ बर्मन ने की थी। जिसमें पूरे घोटाले के बारे में जानकारी दी गई थी।

वहीं रांची के शिव कुमार शर्मा ने नगड़ी थाने में 62 पन्नों का आवेदन 10 फरवरी को दिया था। आवेदन में टीडीपीएल कंपनी, इसके निदेशक रामवीर सिंह, सत्यपाल सिंह, मार्केटिंग मैनेजर अभय तिवारी समेत अन्य लोगों को आरोपी बनाने की मांग की गई थी। लेकिन इन शुरुआती शिकायतों पर न तो आयोग और ना ही रांची की नगड़ी पुलिस ने ही कार्रवाई की। सीआईडी ने अब इन दोनों शिकायतों को भी जांच का हिस्सा बनाते हुए कोर्ट को इसकी प्रति सौंपी है।

अध्यक्ष से की गई थी स्वतंत्र जांच कराने की मांग : जेपीएससी की ओर से आयोजित वन क्षेत्र पदाधिकारी और सहायक वन संरक्षक परीक्षाओं की निष्पक्षता को लेकर गंभीर आरोप सामने आए। आयोग के अध्यक्ष को दी गई एक औपचारिक शिकायत में परीक्षा संचालन से जुड़ी निजी एजेंसी टीडीपीएल और उससे जुड़े कुछ लोगों की भूमिका की स्वतंत्र जांच कराने की मांग की गई थी। ओएमआर उत्तर पुस्तिकाओं में कथित हेरफेर समेत कई आरोप लगाए गए थे।

डिजिटल मूल्यांकन प्रक्रिया में अनधिकृत बदलाव, अयोग्य अभ्यर्थियों को मेरिट सूची में शामिल कराने तथा परीक्षा में चयन के नाम पर कथित रूप से बड़ी रकम मांगने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए थे।

एसीएफ समेत अन्य परीक्षाओं में गड़बड़ी

दोनों शिकायत में सबसे गंभीर आरोपों में टीडीपीएल से जुड़े लोगों पर कथित तौर पर परीक्षा की 150 से अधिक ओएमआर उत्तर पुस्तिकाओं और एफआरओ परीक्षा की 350 से अधिक ओएमआर उत्तर पुस्तिकाओं में विभिन्न स्थानों पर हेरफेर या बदलाव का आरोप लगाया गया था। शिकायतकर्ताओं ने दावा किया है कि इन गतिविधियों को शहर के अलग-अलग स्थानों से संचालित किए जाने की बात सामने आई है। साथ ही, प्रत्येक अभ्यर्थी से प्रारंभिक परीक्षा पास कराने के लिए कथित तौर पर 5 लाख रुपये और अंतिम चयन के लिए लगभग 25 लाख रुपये तक की मांग किए जाने का आरोप लगाया गया था।

SBI भारतीय स्टेट बैंक
एसबीआई गृह ऋण केन्द्र, जमशेदपुर
प्रथम तल, जमशेदपुर शाखा भवन, बिष्टुपुर, जमशेदपुर-831001

अचल संपत्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना

सिक्योरिटाइज़ेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 और सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एनफोर्समेंट) रूल्स, 2002 के नियम 8(6) और 9(1) के प्रावधानों के तहत अचल संपत्ति की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना

आम जनता और विशेष रूप से उधारकर्ता और जमानतदार को सूचित किया जाता है कि नीचे बताई गई अचल संपत्ति, जिसे सुरक्षित लेनदार के पास गिरवी रखा गया था और जिसका भौतिक कब्जा सुरक्षित लेनदार **स्टेट बैंक ऑफ इंडिया** के प्राधिकृत अधिकारी ने ले लिया है, उसे **02.09.2026 (बुधवार)** को **''जैसा है, जहाँ है'', ''जैसा है, वैसा है'' और ''जो कुछ भी है''** के आधार पर बेचा जाएगा। यह बिक्री 02.10.2022 तक बकाया राशि **रु. 17,66,257.13 (सत्रह लाख छियासठ हजार दो सौ सत्तावन रुपये और तेरह पैसे)** की वसूली के लिए की जाएगी, जिसमें 02.10.2022 से लागू ब्याज, लागत, शुल्क और अन्य खर्च जोड़े जाएंगे और 02.10.2022 के बाद उधारकर्ता/जमानतदार से वसूली गई या उनके द्वारा जमा की गई राशि को घटा दिया जाएगा।

उधारकर्ता और जमानतदार का नाम, आरक्षित मूल्य और अग्रधन जमा राशि (Earnest Money Deposit) का विवरण नीचे दिया गया है:

ऋणी एवं जमानतदार का नाम	सम्पत्ति का विवरण (सम्पत्ति आईडी : SBIN88802752706)	आरक्षित मूल्य / ईएमडी / बोली बृद्धि राशि
श्री पलविंदर सिंह एवं श्रीमती अमरजीत कौर	फ्लैट नंबर जी-5, मौजा - बालिगुमा, नेहा अपार्टमेंट, वार्ड नंबर 10 एमएनएसी, नया प्लॉट नंबर 334, नया खाता नंबर 59, थाना - एमजीएम मेडिकल कॉलेज, शहर-जमशेदपुर, जिला-पूर्वी सिंहभूम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम के पास, बालिगुमा.	₹ 14,25,000.00 ₹ 1,42,500.00 ₹ 10,000.00

ई-नीलामी के नियम और शर्तें

1. **ई-नीलामी की तारीख और समय 02.09.2026 (बुधवार), सुबह 11:00 बजे से शाम 04:00 बजे तक, जिसमें हर बार 10 मिनट का अनलिमिटेड एक्सटेंशन (समय बढ़ाने की सुविधा) होगा.**
2. ई-नीलामी के लिए वेबसाइट / पोर्टल - **https://baanknet.com**
3. ई-नीलामी बिक्री की सामान्य शर्तें और नियम इस वेबसाइट पर उपलब्ध हैं: **https://sbi.co.in/web/sbi-in-the-news/auction-notices/sarfaesi-and-others.**
4. **प्रॉपर्टी से जुड़ी जानकारी/सत्यापन के लिए मोबाइल नंबर : 8102076901 / 9031802451**
5. प्राधिकृत अधिकारी की जानकारी और ज्ञान के अनुसार, प्रॉपर्टी पर कोई भार (Encumbrance) नहीं है। हालाँकि, बोली लगाने वालों को अपनी बोली जमा करने से पहले प्रॉपर्टी पर किसी भी भार, मालिकाना हक (Title) और प्रॉपर्टी को प्रभावित करने वाले दावों/अधिकारों/बकाया राशि के बारे में स्वतंत्र रूप से जांच-पड़ताल कर लेनी चाहिए। ई-नीलामी का विज्ञापन बैंक की ओर से कोई वादा या प्रतिनिधित्व नहीं माना जाएगा। प्रॉपर्टी को सभी मौजूदा और भविष्य के भारों (चाहे बैंक को उनके बारे में पता हो या न हो) के साथ बेचा जा रहा है। प्राधिकृत अधिकारी/सुरक्षित लेनदार किसी भी तीसरे पक्ष के दावों/अधिकारों/बकाया राशि के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होंगे। बिक्री ''सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 के तहत निर्धारित नियमों/शर्तों के अधीन होगी।

यह प्रकाशन सिक्योरिटी इंटरेस्ट एनफोर्समेंट रूल्स, 2002 के नियम 8(6) और 9(1) के तहत सभी उधारकर्ताओं/जमानतदार को 15 दिन का नोटिस भी माना जाएगा।

नोट: उधारकर्ताओं/जमानतदार को 15 दिन का बिक्री नोटिस पहले ही उनके आखिरी ज्ञात पते पर रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजा जा चुका है। यदि उन्हें वह नोटिस नहीं मिलता है, तो इस ई-नीलामी बिक्री नोटिस को सर्विस (नोटिस देने) का वैकल्पिक तरीका माना जा सकता है।

ह0/-प्राधिकृत अधिकारी
दिनांक : 18.08.2026, स्थान : जमशेदपुर
प्रकाशन में किसी भी प्रकार के त्रुटि के लिए बैंक जिम्मेवार नहीं होगा।
भारतीय स्टेट बैंक, गृह ऋण केन्द्र जमशेदपुर

परीक्षाओं की हो सीबीआई जांच : रघुवर

मांग

रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर गलत राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि हेमंत ने 2014 से परीक्षाओं की जांच कराने की घोषणा की है। मैं छात्रों की मांग दोहराते हुए पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग करता हूं।

रघुवर ने कहा कि उनके कार्यकाल में जितनी परीक्षाएं हुईं, उनमें किसी में भी धांधली की शिकायत कभी भी छात्रों द्वारा नहीं की गई और ना ही आंदोलन हुआ। छठी जेपीएससी में तकनीकी खामियों जैसे हिंदी और अंग्रेजी के नंबर को जोड़े जाने के सैद्धांतिक निर्णय को लेकर विवाद हुआ था। सीट बेचे जाने या बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोप कभी भी नहीं लगे। मुख्यमंत्री को यदि गड़बड़ियों की शिकायत मिली थी तो वे 2019 से सत्ता संभालने के बाद से क्या कर रहे थे? उन्होंने कोई जांच क्यों नहीं करवाई? अब छात्रों की मांगों को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं।

छात्रों की मांगों को भटकाने की कोशिश कर रही सरकार

रघुवर ने कहा कि सरकार ने नौ अगस्त को 14वीं जेपीएससी पीटी रद्द करने की घोषणा की थी, लेकिन आज तक अधिसूचना जारी नहीं हुई है। इसमें एक पेच है कि परीक्षा सरकार रद्द नहीं कर सकती है। रद्द करने का अधिकार जेपीएससी के पास सुरक्षित है। और जेपीएससी में न तो अध्यक्ष है न ही सदस्य। सीआइडी जांच का उद्देश्य दोषियों को सजा दिलाना नहीं, बल्कि सत्ता में बैठे प्रभावशाली लोगों और नौकरशाहों को बचाना है।

'छात्रों की मांगें जल्द पूरी करे सरकार'

घाटशिला, संवाददाता। ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन (एआईडीएसओ) के झारखंड प्रदेश सचिव सोहन महतो ने हजारों की संख्या में विधानसभा घेराव करने पहुंचे छात्रों की एकजुटता की सराहना की।

उन्होंने सरकार से छात्रों की सभी मांगें मानने की अपील करते हुए कहा कि मांगें पूरी नहीं हुईं तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि झारखंड अलग राज्य बनने के बाद बनी सरकारों के कार्यकाल में जेपीएससी, जेएसएससी और सीजीएल परीक्षाओं में अनियमितता और धांधली के आरोप लगते रहे हैं। इसी कारण मजबूर होकर छात्र आज सड़कों पर उतरने को विवश हैं। आंसू गैस और वाटर कैनन के इस्तेमाल से छात्र डरने वाले नहीं हैं। छात्रों की सभी मांगों को लेकर उनका संगठन आंदोलन के शुरुआती दौर से ही उनके साथ खड़ा है। विधानसभा घेराव में संगठन शामिल हुआ था।

कर्मचारी संघ 20 को घेरेगा निदेशालय

रांची। रांची नगर निगम कर्मचारी संघ विभिन्न मांगों को लेकर गुरुवार को नगरीय प्रशासन निदेशालय का घेराव करेगा। इनकी प्रमुख मांगों में मृत कर्मियों के आश्रितों की अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति, सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन में हुई 20 प्रतिशत कटौती वापस लेने और मृत कर्मियों के विधवा आश्रितों को पारिवारिक पेंशन का लाभ देने की मांग शामिल है।

ये जानकारी मंगलवार को निगम कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में संघ के अध्यक्ष नरेश राम ने दी। उन्होंने बताया कि निगम में 37 आश्रितों में से केवल 16 की नियुक्ति अनुकंपा के आधार पर की जा रही है। आंदोलन को लेकर जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है।